निवेश बढ़ाने को बनेगा निर्यात संवर्धन कोष

फैसला

लखनऊ, विशेष संवाददाता। यूपी सरकार इसी महीने नई निर्यात नीति लाने जा रही है। इसका लक्ष्य 2030 तक निर्यात को बढ़ाकर तीन गुना करना है। इसके तहत एक निर्यात संवर्धन कोष बनेगा।

इसका उपयोग वैश्विक सम्मेलनों में ब्रांड यूपी के संवर्धन के लिए किया जाएगा। साथ ही वार्षिक किस्त के भुगतान के लिए निर्यातकों को 5 लाख रुपये तक की सहायता भी प्रदान की जाएगी। एक वन स्टॉप डिजिटल सूचना केंद्र बनेगा।

यूपी सरकार हर निर्यातक इकाई के लिए सहायता की राशि मौजूदा नीति के 16 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये सालाना करेगी।

निर्यातकों को प्रमुख पत्तनों तक माल परिवहन के लिए हर साल 30 लाख रुपये तक का प्रोत्साहन दिया जा सकता है। विमान लोडिंग के लिए प्रत्येक इकाई को हर साल 10 लाख रुपये तक का अनुदान मिलेगा। निवेशकों को पूंजी अनुदान के रूप में 10 करोड़ रुपये तक प्रदान किए जाने की संभावना है।

खास बातें

- प्रतिभागियों के स्टॉल लगाने पर 3.25 लाख रुपये तक की कुल लागत का 75 फीसदी सरकार देगी
- निर्यात प्रतिभागियों की हवाई यात्रा के लिए भी अधिकतम 1.25 लाख रुपये की सहायता।
- निर्यातकों को वेबसाइट विकसित करने के लिए 75,000 रुपये बजाए एक लाख रुपये

05 लाख रुपये तक की निर्यातकों को सहायता भी प्रदान की जाएगी

इनका कहना है

औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता 'नंदी' ने कहा कि हमने देश के विभिन्न प्रांतों की सरकारों की निर्यात नीतियों का व्यापक अध्ययन कर उनकी सर्वोत्तम कार्यप्रणाली को शामिल किया है। हमारा उद्देश्य देश के समग्र निर्यात में उत्तर प्रदेश के योगदान को काफी हद तक बढ़ाना है और प्रस्तावित नीति इस दिशा में एक अहम कदम होगी।